कार्यकारी आदेश 2025-03

कार्यकारी आदेश
ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति
से उत्पन्न इलिनॉय उपभोक्ताओं पर बढ़ती लागत
और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के समाधान हेतु

चूंकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 से आयात पर कई टैरिफों की घोषणा की है और उन्हें लागू भी किया है ("अमेरिकी टैरिफ"); और,

चूंकि, कुछ देशों—जिनमें चीन जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार शामिल हैं—से होने वाले सभी आयातों पर अमेरिकी टैरिफ 145% तक लगाए गए थे; और,

चूंकि, कई देशों, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी शामिल हैं, ने अमेरिकी वस्तुओं पर—जिनमें इलिनॉय में निर्मित उत्पाद भी शामिल हैं—प्रतिशोधात्मक टैरिफों की घोषणा की है और उन्हें लागू किया है; और,

चूंकि, अमेरिकी टैरिफों ने इलिनॉय के उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा दी हैं, स्थानीय उद्योगों के लिए विनिर्माण लागत में वृद्धि की है, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएँ और स्रोत निर्धारण से जुड़ी चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं, स्थानीय व्यवसायों के लिए लागत बढ़ाई है और इलिनॉय में निर्मित वस्तुओं के निर्यात बाज़ार को कमजोर किया है; और,

चूंकि, अमेरिकी टैरिफ विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर रहे हैं, जिससे विनिर्माताओं और छोटे व्यवसायों के बीच अनिश्चितता पैदा हो रही है और अंततः उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि हो रही है; और,

चूंकि, अमेरिकी टैरिफ और उसके प्रत्युत्तर में लगाए गए प्रतिशोधात्मक टैरिफों ने इलिनॉय की आर्थिक वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं और औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित किया है और उन्हें नुकसान पहुँचाया है; और,

चूँकि, अमेरिकी टैरिफ और उसके प्रत्युत्तर में लगाए गए प्रतिशोधात्मक टैरिफों से होने वाले नुकसान इलिनॉय की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों—जैसे चिकित्सीय आपूर्ति श्रृंखलाएँ, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण कार्य, और विनिर्माण क्षेत्र के सभी पहलू—में आवश्यक आपूर्ति नेटवर्क को गंभीर रूप से बाधित कर रहे हैं; और,

चूँकि, ट्रंप प्रशासन ने न तो इलिनॉय के नीति निर्धारकों से कोई संवाद किया है और न ही यह जानकारी या डेटा उपलब्ध कराया है कि अमेरिकी टैरिफ इलिनॉय की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं;

अतः, इलिनॉय राज्य का राज्यपाल होने के नाते और इलिनॉय संविधान द्वारा मुझे प्रदान किए गए अधिकारों के अंतर्गत, मैं निम्नलिखित आदेश जारी करता हूँ:

I. कार्यान्वयन

राज्यपाल को उनके विचार-विमर्श में सहायता प्रदान करने हेतु, इस आदेश की तिथि से 100 दिनों के भीतर निम्नलिखित एजेंसियों में से प्रत्येक यह विचार करेंगी कि अमेरिकी टैरिफों का इलिनॉय पर क्या विशेष प्रभाव पड़ा है और इन टैरिफों के प्रभाव को कम करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इस पर प्रारंभिक सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेंगी:

इलिनॉय वाणिज्य और आर्थिक अवसर विभाग, इलिनॉय रोज़गार सुरक्षा विभाग के सहयोग से, अपनी सिफ़ारिशें तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा:

- व्यापार से संबंधित परिवर्तनों से सर्वाधिक प्रभावित उद्योगों और आर्थिक विकास क्षेत्रों का आकलन; और
- नई व्यापारिक परिस्थितियों से संबंधित इलिनॉय के व्यवसायों द्वारा रिपोर्ट की गई प्रमुख चुनौतियाँ।

इलिनॉय रोजगार सुरक्षा विभाग, इलिनॉय वाणिज्य और आर्थिक अवसर विभाग के सहयोग से, अपनी सिफ़ारिशें तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगा:

- टैरिफ लागू होने के बाद से रोजगार प्रवृत्तियों का विश्लेषण।

इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अपनी सिफ़ारिशें तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगा:

- उन श्रेणियों का विश्लेषण जिनमें चिकित्सीय आपूर्तियों को आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ा है;
- महत्वपूर्ण आपूर्तियों की कमी या मूल्य में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण;
- उन चिकित्सीय सेवाओं या उत्पादों का विश्लेषण जिन पर मूल्य संबंधी प्रभाव पड़ा है; और
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा आपूर्ति लागत को लेकर जताई गई चिंताएँ।

इलिनॉय मानव सेवा विभाग अपनी सिफ़ारिशें तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगा:

- खाद्य सहायता कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाले खाद्य दान की प्रवृत्तियों और आपूर्ति में हुए बदलावों का अवलोकन;
- फूड बैंकों की क्रय क्षमता और समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता का अवलोकन;
- बढ़ी हुई संचालन लागत के बावजूद सेवाएँ बनाए रखने के लिए खाद्य सहायता कार्यक्रमों द्वारा किए गए उपायों का विश्लेषण; और
- आपातकालीन खाद्य प्रणाली से प्राप्त उनकी सबसे गंभीर आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चुनौतियों पर प्रतिक्रिया।

इलिनॉय परिवहन विभाग अपनी सिफ़ारिशें तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगा:

- अमेरिकी टैरिफ नीति के कारण लागत और समय-सीमा से जुड़ी चुनौतियों के चलते बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पड़े प्रभावों का अवलोकन;
- परिवहन परियोजनाओं में किए गए समायोजन और सामग्री की बढ़ी हुई लागत को प्रबंधित करने के लिए अपनाए गए तरीकों का सारांश; और
- राज्य परिवहन योजना के लिए प्राथमिकता निर्धारण की रणनीतियों का मूल्यांकन और उनके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन।

इलिनॉय कैपिटल डेवलपमेंट बोर्ड अपनी सिफ़ारिशें तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगा:

- निर्माण सामग्री से संबंधित चुनौतियों का अवलोकन, जिसमें शामिल हैं:
    - प्रमुख निर्माण सामग्री जिनके मूल्य या उपलब्धता में गंभीर समस्याएँ देखी गई हैं; और
    - सामग्री की सीमाओं के अनुरूप उद्योग द्वारा किए गए अनुकूलन उपाय।;
- निर्माण परियोजनाओं में किए गए समायोजन का सारांश, जिसमें शामिल हैं:
    - सामग्री लागत में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए अपनाए गए तरीके; और
    - सफल वैकल्पिक स्रोतों या डिज़ाइन रणनीतियों का उपयोग।

इलिनॉय आपात प्रबंधन एजेंसी – होमलैंड सुरक्षा कार्यालय अपनी सिफ़ारिशें तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगा:

- आपातकालीन प्रतिक्रिया आपूर्ति से संबंधित चुनौतियों का अवलोकन, जिसमें शामिल हैं:
    - आपूर्ति या लागत संबंधी चुनौतियों से प्रभावित आपातकालीन सामग्रियों की श्रेणियाँ, तथा किसी भी उल्लेखनीय भंडारण या उपकरण से जुड़ी चिंताएँ; और
- आपातकालीन खरीद समायोजन का सारांश, जिसमें शामिल हैं:
    - महत्वपूर्ण आपूर्तियों के लिए स्रोत निर्धारण रणनीतियों में किए गए बदलाव; और
    - बजट सीमाओं के भीतर आपात तैयारी बनाए रखने के लिए अपनाए गए तरीके।

जहाँ उपयुक्त हो, राज्य अन्य समान परिस्थितियों वाले राज्यों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित करेगा ताकि अपने डेटा और निष्कर्ष साझा किए जा सकें।

जहां उपयुक्त हो, राज्य समान स्थिति वाले राज्यों के साथ समन्वित कार्रवाई का मूल्यांकन करेगा और प्रस्ताव करेगा, जिससे संबंधित राज्य अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके।

II. प्रभावी तारीख

यह सरकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर प्रभावी हो जाएगा।

III. बचाव प्रावधान

इस कार्यकारी आदेश की कोई भी बात किसी भी संघीय या राज्य कानून अथवा विनियम का उल्लंघन करने के रूप में नहीं समझी जाएगी। इस कार्यकारी आदेश की कोई भी बात वर्तमान में प्रभावी अनुबंधों, समझौतों या सामूहिक सौदेबाजी समझौतों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगी।

IV. विच्छेदनीयता

यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

_____

JB Pritzker, राज्यपाल

राज्यपाल द्वारा जारी: 14 जुलाई, 2025
राज्य सचिव के समक्ष दायर: 14 जुलाई, 2025